दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक दैनिक हो गया है। इसका सर्वे का कार्य आगे भी तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 ‖ Postal Registration No-055/Raigarh DN CG ‖ रायगढ़, शनिवार 26 अक्टूबर 2019 ‖ पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए ‖ वर्ष-02, अंक- 30

महत्वपूर्ण एवं खास

प्रमोद कुमार दास ने संभाला अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का पदभार

नईदिल्ली (आरएनएस)। प्रमोद कुमार दास ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के सचिव का शुक्रवार को नई दिल्ली में पदभार संभाल लिया। इससे पहले वह वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में विशेष सचिव थे। दास भारतीय प्रशासनिक सेवा के मध्य प्रदेश कैडर के 1986 बैच के अधिकारी हैं। वह केन्द्र और राज्य सरकारों में अनेक अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। इनमें केन्द्र में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग में अपर सचिव, डीओपीटी और उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव तथा भोपाल में व्यापार और निवेश सुविधा कार्पोरेशन लिमिटेड में प्रबंध निदेशक और राज्य औद्योगिक विकास निगम भोपाल में प्रबंध निदेशक, श्रम विभाग में श्रम आयुक्त और व्यावसायिक कर विभाग इंदौर के आयुक्त का पद शामिल है।

जस्टिस कुरैशी की पदोन्नति मामले की सुनवाई चार नवंबर तक स्थगित

नईदिल्ली (आरएनएस)। उच्चतम न्यायालय ने न्यायमूर्ति अकिल कुरैशी को त्रिपुरा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति के मामले में याचिका की सुनवाई चार नवंबर तक के लिए आज स्थगित कर दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के लिए चार नवंबर की तारीख उस वक्त निर्धारित की जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायालय को बताया कि वह न्यायमूर्ति कुरैशी की पदोन्नति के मामले में सरकार से निर्देश हासिल करके उसे अवगत कराएंगे। कॉलेजियम द्वारा नए सिरे से सिफारिश के 50 दिन बाद भी सरकार की ओर से उनकी नियुक्ति का वारंट जारी नहीं हो सका है।

गिरीश चंद्र मुर्मू जम्मू-कश्मीर के पहले उपराज्यपाल नियुक्त

» सत्यपाल मलिक का गोवा ट्रांसफर

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के वरिष्ठ अधिकारी गिरीश चंद्र मुर्मु को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर तथा वरिष्ठ आईएएस अधिकारी राधा कृष्ण माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति भवन की ओर से आज जारी विज्ञप्ति के अनुसार, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात कैडर के 1985 बैच के आईएएस अधिकारी मुर्मु को जम्मू-कश्मीर और त्रिपुरा कैडर के 1977 बैच के आईएएस अधिकारी माथुर को लद्दाख का उपराज्यपाल नियुक्त किया है। भाजपा की केरल इकाई के अध्यक्ष पी एस श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जम्मू-कश्मीर के मौजूदा राज्यपाल सत्यपाल मलिक अब गोवा के राज्यपाल होंगे। मलिक को 2018 में कुछ महीनों के लिए ओडिशा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था। सत्यपाल मलिक 1980-86 और 1986-1992 तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य रहे। वह 1974 से 1977 तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी रहे हैं। वहीं पी.एस. श्रीधरन पिल्लई को मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया है।

महाराष्ट्र नहीं हरियाणा में सरकार बनाने की संभवना तलाशें:सोनिया

नईदिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव परिणामों को लेकर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कांग्रेस के नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने को लेकर उत्साहित न हों. सिर्फ सरकार बनाने की बेचैनी नहीं दिखे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनानी ही है तो हरियाणा में संभावनाओं की तलाश करें. सोनिया ने इस दौरान नेताओं को शांत रहने और समय के अनुरूप काम करने की सलाह दी. गौरतलब है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस व एनसीपी के खाते में 104 सीटें आई हैं और बहुमत का आंकड़ा 145 पार है. वहीं हरियाणा में पार्टी को 31 सीटें मिली हैं. यहां पर सरकार बनाने के लिए 46 सीटों की जरूरत रहेगी.

दिवाली, छठ त्योहार के लिए 200 स्पेशल ट्रेनें चला रहा रेलवे

» 2,500 से अधिक फेरे

नईदिल्ली (आरएनएस)। भारतीय रेलवे ने त्यौहार मनाने के लिए परिवार के साथ अपने गृह नगर जा रहे यात्रियों के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। रेल यात्रियों की सुविधा और त्यौहार के मौसम के दौरान यात्रियों की भीड़ कम करने के लिए, भारतीय रेलवे इस वर्ष दुर्गा पूजा से क्रिसमस तक 200 जोड़े विशेष ट्रेनें चला रहा है। साथ ही उसने नियमित ट्रेनों में कोचों की संख्या बढ़ाई है ताकि त्यौहार के दौरान होने वाली भीड़ के लिए बर्थ उपलब्ध कराई जा सके।

भारतीय रेलवे देश भर में 200 जोड़े विशेष ट्रेनों में 2500 अतिरिक्त सेवाएं चला रहा है। देश के प्रमुख स्थानों जैसे दिल्ली-पटना, दिल्ली-कोलकाता, दिल्ली-मुम्बई, मुम्बई-

लखनऊ, चंडीगढ़-गोरखपुर, दिल्ली-छपरा, हावड़ा-कटिहार, हरिद्वार-जबलपुर आदि को जोड़ने के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेनों की योजना बनाई है।

अनारक्षित डिब्बों में यात्रियों का प्रवेश अनुशासित तरीके से कराने के लिए आरपीएफ कर्मचारियों की देखरेख में टर्मिनस स्टेशनों पर पंक्तियां बनाकर भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा।

यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों में आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं।

सुरक्षाकर्मियों के साथ इंजीनियरिंग, सिगनल और दूरसंचार विभागों के अतिरिक्त कर्मचारियों को भीड़भाड़ वाले रेलवे सेक्शनों में महत्वपूर्ण रेलवे क्रॉसिंग पर तैनात किया गया है।

रेल और सड़क का इस्तेमाल करने वालों की सुविधा के लिए स्टेशनों और प्रमुख रेलवे क्रॉसिंग पर प्रकाश के पर्याप्त प्रबंध किए गए हैं। ट्रेनों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर अधिकारियों को तैनात किया गया है। ट्रेन सेवा में किसी प्रकार की बाधा से निपटने के लिए प्राथमिकता के आधार पर विभिन्न सेक्शनों में कर्मचारियों की तैनाती की गई है।

प्लेटफॉर्म संख्या के साथ ट्रेनों के आगमन/रवाना होने के समय की घोषणा कराने के भी उपाय किए गए हैं।

महत्वपूर्ण स्टेशनों पर क्या मैं आपकी मदद कर सकता/सकती हूं बूथ भी काम करेंगे जहां आरपीएफ जवान और टीटीई यात्रियों की उपयुक्त सहायता और मार्गदर्शन करेंगे। जरूरत पड़ने पर प्रमुख स्टेशनों में चिकित्सकों के दल उपलब्ध होंगे। अर्द्धचिकित्सकों के साथ एम्बुलेंस भी उपलब्ध रहेगी। मेल/एक्सप्रेस/यात्री ट्रेनों को निर्धारित समय पर रवाना करने के उपाय किए गए हैं। किसी तरह के भ्रष्टाचार जैसे सीट बेचने, ओवर चार्जिंग और दलाली आदि पर सुरक्षा और सतर्कता विभाग के अधिकारियों द्वारा कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

मानवाधिकार और सूचना समेत 7 आयोग होंगे खत्म

» जम्मू-कश्मीर पर सरकार का बड़ा फैसला

श्रीनगर (आरएनएस)। जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राज्य के विकास को लेकर सरकार की तरफ से कई अहम फैसले लिए गए हैं। ताजा फैसले में जम्मू-कश्मीर से प्रशासन ने सात आयोग को खत्म करने का फैसला किया है, जिनमें मानवाधिकार आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग और सूचना आयोग को भी शामिल किया गया है। जम्मू-कश्मीर में 31 अक्टूबर से नए कानून लागू हो जाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से राज्य में जो कानून लागू नहीं होते थे, वह अब राज्य में लागू किए जा सकेंगे। नई व्यवस्था के तहत जम्मू-कश्मीर को मुख्यधारा में वापस लाने और राज्य के विकास के लिए कई बड़े बदलाव करने का फैसला किया गया है। इन्हें फैसलों के तहत जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने बुधवार को सात आयोग खत्म करने का आदेश जारी कर दिया है।

जानकारी के मुताबिक, सरकार ने जिन आयोग को खत्म करने का फैसला किया है उनमें जम्मू-कश्मीर मानवाधिकार आयोग, राज्य सूचना आयोग, राज्य उपभोक्ता निवारण आयोग, राज्य विद्युत नियामक आयोग, महिला एवं बाल विकास आयोग, दिव्यांग जनों के लिए बना आयोग और राज्य पारदर्शिता आयोग शामिल हैं।

गौरतलब है कि 31 अक्टूबर को जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बन जाएगा। ऐसे में वहां पर केंद्र सरकार की ओर से तय कानून लागू किए जा सकेंगे। बताया जाता है कि जिन आयोग को खत्म किया गया है वह केंद्र के अधीन होंगे और केंद्र सरकार की ओर से तय नियमों के हिसाब से ही यहां पर काम किया जाएगा।

पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप /डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने कोई विज्ञापन जारी नहीं

नईदिल्ली (आरएनएस)। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के संज्ञान में आया है कि कुछ अवांच्छित लोगों ने 'एलपीजी वितरक केन्द्र' के जरिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के नाम और लोगों का इस्तेमाल करते हुए पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए अनुमोदन पत्र जारी किया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिप / डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए कोई विज्ञापन जारी नहीं किया है। आगे और स्पष्ट किया जाता है कि डीलरशिप/ डिस्ट्रीब्यूटरशिप नियुक्त/प्रदान करने के विषय में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की कोई भूमिका नहीं होती। तेल विपणन कंपनियां व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर स्थानों की पहचान करती हैं तथा संबंधित चयन दिशा-निर्देशन के अनुसार डीलरों के लिए विज्ञापन जारी करती हैं।

इसलिए आम जनता को सलाह दी जाती है कि वह ऐसे विज्ञापन/अनुमोदन पत्र पर कोई ध्यान न दें।

संसद भवन और अन्य भवनों के पुनर्विकास के लिए समय सीमा तय

नईदिल्ली (आरएनएस)। संसद भवन तथा एकीकृत केन्द्रीय सचिवालय के पुन निर्माण और सेंट्रल विस्टा के पुर्नविकास के लिए सख्त समय सीमा तय कर दी गई है। लोकनिर्माण विभाग को जहां सेंट्रल विस्टा परियोजना को का काम नवंबर 2021 तक पूरा करने के लिए कहा गया है वहीं नए संसद भवन का निर्माण मार्च 2022 तक तथा एकीकृत केन्द्रीय सचिवालय का काम मार्च 2024 तक पूरा होना है।

सरकार ने इस योजना के लिए परामर्श सेवा का ठेका मेसर्स एचसीपी डिजाइन, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को दिया है। कंपनी को केन्द्र

द्वारा तय नियमों और जरूरतो के अनुरूप यह काम तय समय में पूरा करना है।

नये मास्टर प्लान के तहत रायसीना हिल्स पर स्थित पुराने सरकारी भवनों के साथ ही संसद और सचिवालय को नया रूप देकर सांसदों के लिए आवश्यकता अनुसार पर्याप्त जगह की व्यवस्था की जाएगी। इस काम के लिए एक विश्वस्तरीय सलाहकार सेवा की जरूरत थी लिहाजा सरकार ने इसके लिए कंपनियों के चयन की प्रक्रिया 2 नवंबर 2019 से शुरु कर दी थी। केन्द्रीय लोकनिर्माण विभाग ने इस दिन कंपनियों से निविदा आमंत्रित की थी। निविदा के लिए क्यूसीबी (80:20) प्रक्रिया का अनुकरण किया गया। परामर्श सेवा के लिए 229.75 करोड़ रूपए की राशि निर्धारित की गई। आरएफपी के तहत 12नवंबर 2019 को निविदा पूर्व बैठक आयोजित की गयी जिसमें 24 बोलीकर्ताओं ने भाग लिया और उनके द्वारा उठाए गये मुद्दों का निराकरण किया गया। तकनीकी निविदा 30 नवंबर 2019 को शुरू की गयी। शुरूआती अर्हताओं और तकनीकी मानकों की जांच के बाद सभी बोलीकर्ताओं से अपनी निविदा अपनी निविदाएं एक ज्यूरी के समकक्ष रखने को कहा गया। इस ज्यूरी में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के अध्यक्ष प्रोफेसर पीएसएन राव की अध्यक्षता में जाने माने लैंडस्केप डिजाइनर और आर्किटेक्ट शामिल थे। आखिर में अंतिम बोली प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिए चार बोलीकर्ताओं का चयन किया गया।

आईआरएस अधिकारियों के समूह ने की डॉ. जितेन्द्र सिंह से मुलाकात

नईदिल्ली (आरएनएस)। 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारियों (सीमा शुल्क और अप्रत्यक्ष कर) के एक समूह ने शुक्रवार को केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास (स्वतंत्र प्रभार), कार्मिक, जन शिकायतें और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह से मुलाकात की। बैठक के दौरान अधिकारियों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ अपनी सेवा से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों के बारे में विचार विमर्श किया।

बैठक के दौरान इन अधिकारियों ने डॉ. जितेन्द्र सिंह के साथ अपनी सेवा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री को उस नियम के बारे में बताया जिसमें एसटीएस से जेएजी तक पदोन्नत होने के लिए एसटीएस में अनिवार्य रूप से 5 साल की सेवा की जरूरत होती है। अधिकारियों ने उनसे अनुरोध किया कि 5 साल की इस अनिवार्यता से छूट दी जाए। उन्होंने यह भी कहा कि एसटीएस से अधिकारियों की पदोन्नति के बाद 2016 में संशोधन द्वारा जेएजी में पदोन्नति के लिए एसटीएस में 5 साल की सेवा की अनिवार्यता को भर्ती नियमों में शामिल किया गया था। विचार-विमर्श के बाद उन्होंने आईआरएस अधिकारियों को शीघ्रता से पदोन्नति दिए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनके मामले में तेजी लाई जाएगी और निर्धारित समय में पदोन्नति दी जाएगी। डॉ. जितेन्द्र सिंह ने कहा कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग पदोन्नति में ठहराव को रोकने की दिशा में काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष की शुरुआत में विभिन्न स्तरों पर काम करने वाले लगभग 4,000 सरकारी अधिकारियों को पदोन्नत किया गया है।

हरियाणा में भाजपा आज गवर्नर से मिलकर पेश करेगी सरकार बनाने का दावा

» गोपाल कांडा पर उमा भारती को आपत्ति

नईदिल्ली (आरएनएस)। हरियाणा में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इन्हीं तैयारियों को लेकर दिल्ली में भाजपा के दिग्गज जुटे हुए हैं। भाजपा के अनिल जैन ने हरियाणा में सरकार के गठन को लेकर कहा है कि चंडीगढ़ में आज सुबह 11 बजे विधायक दल की बैठक होगी। ऑब्जर्वर के रूप में निर्मला सीतारमण और जनरलसेकी अरुण सिंह होंगे। आज ही विधायक दल का नेताचुना जाएगा। उसके बाद हम हरियाणा में सरकार बनाने के लिए गवर्नर से मुलाकात करेंगे। हरियाणा के निर्दलीय विधायक रणधीर गोलन ने भाजपा को समर्थन देने पर कहा है कि मैं 30 साल से भाजपा का कार्यकर्ता था। मैं बीजेपी में था, कहां गया था बीजेपी मेरी मां है। उधर, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उमा भारती ने हरियाणा में पार्टी की सरकार के गठन के लिए बलात्कार एवं हत्या के आरोपी विधायक गोपाल कांडा का समर्थन लिए जाने की कोशिशों पर गहरी आपत्ति व्यक्त करते हुए पार्टी को सलाह दी है कि वह सत्ता के लिए अपने नैतिक आधार को ना भूले और बेदाग लोगों के साथ सरकार बनाए। गंगा के किनारे हिमालय में प्रवास कर रहीं पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुश्री भारती ने ट्विटर पर लगातार आठ ट्वीट करके हरियाणा एवं महाराष्ट्र के चुनाव परिणामों पर अपनी राय आज सामने रखी। उन्होंने कहा, ...मुझे जानकारी मिली है कि हम हरियाणा में भी सरकार बना सकते हैं।

वश्व शांति स्तूप एकता, शांति और अहिंसा का प्रतीक: कोविन्द

» विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती समारोह

नईदिल्ली (आरएनएस)। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शुक्रवार को बिहार के राजगीर में विश्व शांति स्तूप के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह को संबोधित किया।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कहा कि विश्व शांति स्तूप एकता, शांति और अहिंसा का प्रतीक है। इसके संदेश में ऐसी सार्वभौमिकता है जो संस्कृतियों,धर्मो और भौगोलिक सीमाओं के दायरे में सिमटी हुई नहीं है। यह जापान और भारत जैसी शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के बीच साझेदारी और व्यापक सहयोग को भी

दर्शाता है।

कोविंद ने कहा कि महात्मा बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का दर्शन न केवल दुनिया के आध्यात्मिक परिदृश्य में बड़े परिवर्तन का कारण बना बल्कि इसके साथ ही इसने सामाजिक राजनीतिक और कारोबारी नैतिक मूल्यों को स्थापित करने में भी बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि महात्मा बुद्ध के संदेश दुनियाभर में मौजूद उनके 50 करोड़ से ज्यादा अनुयायियों से भी अधिक लोगों तक पहुंचे हैं। बुद्ध के जीवन से संबंधित स्थानों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करना उनके संदेशों की मूल भावना के प्रति लोगों और विशेषकर युवाओं को आकर्षित करने का एक प्रभावी तरीका है।

राष्ट्रपति ने कहा कि विकास के लिए शांति जरूरी है। उन्होंने कहा कि बुद्ध के शांति के संदेश का सार बाह्य शांति के लिए आंतरिक शांति को जरूरी बताता है। आध्यात्मिकता , शांति और विकास एक दूसरे के संबल हैं जबकि संघर्ष,अशांति और विकास की कमी एक दूसरे की वजह बनते हैं। उन्होंने लोगों से गरीबी और संघर्ष को कम करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देने की अपील की।

मां ने अपने ही बेटे की गला घोंटकर कर दी हत्या

» पति से चल रहा था विवाद

ठाणे (आरएनएस)। ठाणे जिले के बदलापुर में हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है जहां एक मां ने अपने ही आठ साल के बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार, 35 वर्षीय महिला ने इस घटना को उस समय अंजाम दिया जब उसका बेटा सो रहा था। पुलिस ने बताया कि हत्यारोपी गृहिणी शीतल मनेर अपने बेटे अर्नव के साथ बदलापुर में अपनी बहन के घर रह रही थी। उसका अपने पति से काफी समय से विवाद चल रहा है। इस वजह से वह काफी दिनों से तनाव और अवसाद से गुजर रही थी।

पुलिस के अनुसार, इसी अवसाद की चलते महिला ने अपने आठ वर्षीय बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

स्वास्थ्य मंत्रालय 28 अक्तूबर से 2 नवम्बर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा

नईदिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी), भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाएगा। इस वर्ष के सतर्कता जागरूकता का विषय ईमानदारी-एक जीवनशैली है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आरंभ केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री द्वारा मंत्रालय के अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने तथा ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के लिए प्रतिबद्धता की 'ईमानदारी शपथ' दिलाने के साथ होगा। इस मंत्रालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देने का भी प्रस्ताव है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग का लक्ष्य सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है। सार्वजनिक जीवन में शुचिता को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार मुक्त समाज की स्थापना करने के अपने प्रयासों के तहत, सीवीसी हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन जनता के बीच जागरूकता उत्पन्न करता है और सभी हितधारकों को सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार को रोकने और उसके खिलाफ संघर्ष करने के लिए प्रोत्साहित करता है।